"सकारात्मक सोच के साथ की गई चर्चा सदैव विकासोन्मुखी होती है। : अटल बिहारी वाजपेयी

लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 सितंबर 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक-25

बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की ओर बढ़ते कदम

3

आत्मनिर्भर होती महिलाएं

7

सुल्तानपुर और भिंडावास को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

8

मनोहर सरकार के 2500 दिन

अंत्योदय, सुशासन, पारदर्शिता

यही रहेगा मूल मंत्र

विशेष प्रतिनिधि

'सबका साथ सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ चली वर्तमान राज्य सरकार अपने सफल एवं गौरवमयी कार्यकाल के 2500 दिन पूरे करने जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में सरकार ने इस दौरान विकास के जो अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए वे निसंदेह अंतिम छोर तक के व्यक्ति को सुकून देने वाले साबित हुए। राजकाज के इतिहास पर अगर कुछ दृष्टि डाली जाए तो यह पहला ऐसा शासन-प्रशासन है जिसकी नीयत पर अंतर्मन से कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। यह सब संभव हुआ समेकित भाव व नेक विचार से। मुख्यमंत्री ने शुरूआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के 'जीरो टोलरेंस' की नीति पर काम करते हुए आगे बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल में बेशक उनकी अपनी पार्टी के विधानसभा सदस्यों की संख्या कम रही मगर उन्होंने साफगोई व पारदर्शिता के सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। सहयोगी दल ने भी उनका बखूबी साथ देते हुए प्रदेश को सुशासन वाली व्यवस्था देने का काम किया। संगठित राज्य सरकार 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' की नीति पर निरंतर आगे बढ़ी, जिसका परिणाम आज यह है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भी प्रदेश का चौतरफा विकास हुआ है। इतना ही नहीं अनेक योजनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भी मिल रही है।

कर्म के मार्ग पर चलते रहने का संकल्प लिया हो तो कालखंड या समय की गणना नहीं होती। कुछ मोड़ आते हैं जहां थोड़ा पीछे की ओर नज़र दौड़ानी होती है कि कहीं कोई कोताही तो नहीं हुई।

हरियाणा सरीखे संवेदनशील व कर्मनिष्ठ राज्य में यह दबाव सदा बना रहता है कि यह वैदिक ऋचाओं एवं श्रीमद् भागवत गीता की पुण्य भूमि है।

अनेक संतों, गुरुओं की वाणी व सरस्वती की लहरें यहां के पर्यावरण को समृद्ध करती रही हैं। साथ-साथ संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी और आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में तेज़ी से आ रहे बदलावों ने भी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

इन 2500 दिनों में सबने मिलकर एकजुट प्रयास किया है कि लोक प्रशासन की प्रणाली समय की मांग के अनुरूप बदले। बदलावों की ताजा बयार में सांस ली जाए और परंपरा व आधुनिकता के बीच एक सुदृढ़ पुल का निर्माण करते हुए आगे बढ़ें।

भारतीय जनमानस स्वतंत्रता का 'अमृत महोत्सव' मना रहे है। स्वाधीनता सेनानियों को नमन् करते हुए यह कर्त्तव्य बनता है कि देश प्रदेश की विकास यात्रा को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाया जाए। चिकित्सा, शिक्षा, तकनीक, उद्योग व कृषि क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। बदलाव में योगदान देने वाले महानुभावों को प्रणाम करना हम सबका दायित्व है।

राज्य सरकार की ओर से 2500 दिनों की कर्मयात्रा पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। मगर अभी अनेक ऐसे लक्ष्य हैं जो स्पष्ट हैं और उनके क्रियान्वयन के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।

राज्य सरकार की ओर से आने वाले दिनों का 'रोडमैप', दिशाबोध, पूरी व्यवहारिकता और गंभीरता के साथ तैयार किया गया है। इस मार्ग पर चलते हुए यही प्रयास होगा कि प्रदेश का सौहार्दपूर्ण माहौल जीवन की मुख्यधारा बने। सभी जन स्वस्थ, स्वाभिमान एवं स्वावलंबन का जीवन जिएं। पुरातत्व-शोध एवं धरोहर-संरक्षण भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। हड़प्पा सभ्यता की प्रतीक राखीगढ़ी से कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर गूंजते गीता के संदेश समूची वैद्धिक सभ्यता से जुड़े अन्य पावन स्थल और विश्वभर में अहिंसा एवं शांति के संदेशवाहक गौतमबुद्ध के स्मृति स्थलों पर समुचित विकास, प्रौद्योगिकी के बोध के साथ जोड़कर किया जाएगा।

योजनाओ का फायदा अंतिम छोर तक पहुंचाना लक्ष्य

सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में हमारी सफलता की एकमात्र कसौटी है, पंक्ति के अंतिम छोर पर पहुंचना। यदि हमारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को शोषित, उपेक्षित, वंचित एवं पिछड़े वर्ग तक नहीं पहुंचाया जाता तो हमारा श्रम सफल नहीं कहला पाएगा।

महान अर्थशास्त्री एवं पंडित दीन दयाल उपाध्याय के दर्शन पर आधारित 'दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना' राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) पर आधारित है।'

इस योजना के तहत 'गरीबों एवं वंचितों की निशानदेही' के लिए पांच विशेष समूह बनाए गए हैं। इन समूहों का 'नेट-वर्क' मजबूत है। इस कवायद में असली गरीब पहचाना जाएगा। उसे पूरा लाभ दिया जाएगा और यह सुनिश्चित बनाया जाएगा कि आने वाले समय में वह गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाए। ये पांचों समूह स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और उसकी जानकारी हम सरकार के पोर्टल पर डालते रहेंगे।

'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत हर गरीब को छह हजार रुपए सालाना दिए जा रहे हैं। हरियाणा में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि केंद्र व राज्य सरकार की जीवन सुरक्षा योजनाओं का प्रीमियम इस योजना की राशि से स्वयंमेव कटता रहे। जब कोई विपत्ति आएगी तो बीमे से मिली धनराशि परिवार को राहत प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री, अंत्योदय परिवार अभियान उत्थान योजना के तहत गरीब परिवारों की वार्षिक से कम आय वाले 48 हजार परिवारों की पहचान कर ली गई है।

मानसून सत्र में 11 विधेयक पारित

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कार्य उत्पादकताकी दृष्टि से उत्कृष्ट रहा। सदन में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच स्वस्थ चर्चा के चलते कुल 11 विधेयक पारित हुए। इनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2021, हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2021, हरियाणा परिवार पहचान विधेयक, 2021 (यथासंशोधित) और हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2021 शामिल हैं।

इनके अलावा हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं व अवसंरचना का प्रबंधन विशेष उपबंध संशोधन विधेयक,2021, महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक, 2021, हरियाणा लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021 और पंडित लखमीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक संशोधन विधेयक, 2021 रहे।

फसल भंडारण के लिए गोदाम

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खरीद एजेंसियों की कवर्ड-क्षमता को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने के लिए नये गोदामों और स्टील साइलों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य की खरीद एजेंसियां, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन व भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करती हैं। इन सभी एजेंसियों के पास लगभग 90.74 लाख मीट्रिक टन कवर्ड भण्डारण क्षमता है। खरीद एजेंसियों द्वारा प्रत्येक वर्ष करीब 70 से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 55 से 65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाती है। इसके अलावा, एजेंसियों द्वारा बाजरा और मक्का भी खरीदा जाता है। राज्य सरकार द्वारा 31.10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम व स्टील साइलों बनाने की प्रक्रिया जारी है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का हिसार में 16632 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष करीब 24,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। हैफेड के 4.41 लाख मीट्रिक टन तथा हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के 2.40 लाख मीट्रिक टन के गोदाम भी निर्माणाधीन है, जिनका कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। कृषि तथा सिंचाई विभाग की रोहतक जिला के गांव नयावास, कैथल जिला के गांव सन्तोख माजरा, हिसार जिला के हांसी तथा करनाल की लगभग 45 एकड़ भूमि को गोदाम बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है। इन गोदामों की 1.50 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता होगी।

संपादकीय

औद्योगिक विकास के नए आयाम

तीव्रता के साथ हो रहे विकास वाले देश में आर्थिक विकास की तीव्र गतिशीलता के दृष्टिगत हरियाणा देश में एक सुदृढ़ वित्तीय-शक्ति के रूप में उभरा है। रोजगार के नए अवसर, आर्थिक सुधार और बड़े, मध्यम व लघु उद्योगों का समुचित विकास, इन सबमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की भूमिका एक मार्गदर्शक, प्रोत्साहक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने वाले नेता के रूप में सामने आई है।

सभी औद्योगिक संस्थानों (एमएसएमई) को नई इकाइयां लगाने, स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता के साथ-साथ अपने उत्पादों को घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की मांग के अनुसार तैयार करने और औद्योगिक विकास की हरियाणा की नीति को नई ऊंचाई देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए एक समर्पित निदेशालय, स्वस्थ पर्यावरण में पूर्ण सफलता दिलाने के लिए कार्यरत है।

मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व ने प्रदेश के सर्वांगीण आर्थिक विकास और ज़मीनी स्तर पर नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन का वातावरण तैयार किया है। सभी स्तरों की औद्योगिक इकाइयों को हर स्तर पर पूर्ण सुविधा एवं मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई का एक निदेशालय स्थापित किया गया है। ऐसे निर्णय से हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु सरीखे उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने सभी स्तरों के औद्योगिक विकास के लिए अलग से सरकारी ढांचा खड़ा किया है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्य' म-f' यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2020 में हरियाणा को तेज़ी के साथ विकास की मार्ग पर अग्रसर तीन सर्वश्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हरियाणा सरकार ने सभी स्तरों पर एमएसएमई के समुचित विकास के लिए अनेक द्वार खोल दिए हैं। एमएसएमई की महत्त्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत अनेक रियायतों की घोषणा की गई है। इनमें सभी इकाइयों के लिए भारतीय लघु-उद्योग-विकास बैंक के माध्यम से बैंक ऋणों की राज्य-गारंटी देना, कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए 20 किलोवाट तक 4.75 रुपए प्रति यूनिट की बिजली दरें तय करना और फैक्ट्रियों में ही श्रमिकों के अस्थायी आवास की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।

- डा चंद्र त्रिखा

मॉडर्न पंचायत भवन बनाने की तैयारी

राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद को सशक्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर 'मॉडर्न पंचायत भवन' बनाए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिला परिषद के चेयरमैन के साथ-साथ पार्षदों के बैठने के लिए भी अलग-अलग कमरे बनाए जाएंगे ताकि वहां बैठकर वे अपने-अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं का खाका तैयार कर सकें। उन्होंने बताया कि इन 'मॉडर्न पंचायत भवनों' में संबंधित विभाग के कार्यालय, बैठक-हॉल, प्रदर्शनी-हॉल, स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए दो दुकानें तथा जिम-कम-योगा हॉल बनाया जाएगा।

चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार शक्तियों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखती है, इसलिए पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अनेक अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन संस्थाओं को स्वच्छता, जल संरक्षण, फसल अवशेष जलाने में कमी लाने जैसे विभिन्न कार्यों पर निगरानी रखने की शक्तियां प्रदान की हैं। उन्हें गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं।

सीएम मनोहरलाल ने लिया केयू में दाखिला

मुख्यमंत्री मनोहरलाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जापानी भाषा में सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स करेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय में इस सर्टिफिकेट कोर्स का शुभारंभ भी किया और दाखिला भी लिया। उन्होंने कहा कि इस कोर्स के पूरा होने के बाद वह भी कुवि एल्युमनी एसोसिएशन के मानद सदस्य नहीं रहेंगे। पूर्व छात्र होने के नाते वह इस एसोसिएशन के सदस्य कहलाएंगे।

उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पूर्व छात्र पुनर्मिलन 2021 समारोह को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुवि ने एल्युमनी मीट का आयोजन करके पुराने विद्यार्थियों को एक मंच पर लाने का सफल प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विधि में नई शिक्षा नीति के तहत केजी-टू-पीजी स्कीम को भी लांच किया और नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए चलाए जाने वाले जापानी भाषा के सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स, बीबीए आनर्स तथा एमटेक डिफेंस टेक्नोलाजी कोर्स को लांच किया।

परिवार पहचान पत्र योजना में डाटा के सत्यापन की प्रक्रिया जारी

परिवार पहचान पत्र योजना के तहत आय डाटा के लिए सत्यापन प्रक्रिया जारी है। 18 अगस्त, 2021 तक परिवार पहचान पत्र में 54,73,599 परिवारों द्वारा अपने परिवार के 2,20,48,121 व्यक्तियों की आय स्व-घोषित की है, जिनकी कुल आय 1,35,724 करोड़ रुपए है। गणितीय फार्मूले से गणना करे तो प्रति व्यक्ति आय और प्रति परिवार आय ' मशः 61,558 रुपए और 2,47,962 रुपए है।

18 अगस्त 2021 तक 29 लाख 84 हजार 533 व्यक्तियों वाले 9लाख 20 हजार 569 परिवारों ने पंजीकरण और परिवार पहचान पत्र में अपना डाटा अपडेट किया लेकिन उनकी हस्ताक्षरित सहमति अभी बाकी है।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने यह जानकारी मानसून सत्र के दौरान देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है। योजना के सर्वे के तहत अब तक 50000 रुपए तक वार्षिक आय वाले 30000 परिवार और एक लाख रुपए तक वार्षिक आय घोषित करने वाले परिवार चिन्हित किये गए हैं।

मेरा परिवार → समृद्ध परिवार

स्व-घोषित आय को केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए एवं रखे जा रहें अन्य उपलब्ध डाटाबेस से डिजिटल माध्यम से और विशेष रूप से गठित समितियों द्वारा भौतिक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। आय का सत्यापन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर 2020 को जारी अधिसूचना संख्या 90/2020एस.0 4545(ई) के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के आयकर डाटाबेस के साथ डिजिटल माध्यम से भी सत्यापित किया जाता है।

भौतिक क्षेत्र के सत्यापन एक सोफटवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इस एप्लिकेशन पर विशेष रूप से गठित टीम, जिसका नाम लोकल कमेटी है, वह कार्य कर रही है। स्थानीय समिति (एलसी) की संरचना ऐसी है कि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें एक सरकारी कर्मचारी शामिल होता है जो टीम लीडर के रूप में कार्य करता है और इसके अलावा टीम में आई.टी. का ज्ञान रखने वाला आपरेटर, एक स्वयंसेवी, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक छात्र शामिल होता है।

हर स्थानीय समिति का प्रत्येक सदस्य परिवार के हर सदस्य की आय के आकलन का ब्यौरा देता है। जहां तीन या अधिक स्थानीय समिति के सदस्यो का आय निर्धारण मेल खाता है, उसे सत्यापित आय के रूप में लिया जाता है। ऐसे मामलों में जहां अंतर होता है, वहां पारिवारिक आय एक निर्धारित फार्मूले के आधार पर निकाली जाती है।

नागरिक सेवाएं प्रदान करना होगा आसान

परिवार पहचान पत्र डाटाबेस सभी सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों के वितरण के लिए काम करता है।

वर्तमान में पीपीपी के साथ सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों का एकीकर्ण किया जा रहा है और अगले तीन महीनों में यह कार्य पूरा होने की सम्भावना है। एकीकरण पर, दस्तावेजों की आवश्यकता के बिना ही किसी भी समय, कहीं भी, सर्' य रूप से नागरिक सेवाएं प्रदान करना संभव होगा क्योंकि पीपीपी डाटाबेस के साथ उपलब्ध डाटा पूर्व-सत्यापित होता है।

डाटा पूरी तरह सुरक्षित

डाटा का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है और किसी निजी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाता है। परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में डाटा सरकारी कलाउड पर सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। पोर्टल केवल अधिकृत उपयोगकर्ता के आधार पर कार्य करता है और इस पर संग्रहीत डाटा तक किसी को खुली पहुंच प्रदान नहीं की गई है। सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन कार्यालय द्वारा स्वयं विकसित की गई है और किसी भी वेडंर विक्रेता को पीपीपी के साथ शामिल नहीं किया गया है।

-संवाद ब्यूरो

सलाहकार संपादक :	डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक :	मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम :	संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक :	सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन :	गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट :	विकास डांगी

पीजीआईएमएस रोहतक समेत राजकीय विश्वविद्यालयों अन्य संस्थानों को ऑनलाइन स्थानांतरण नीति में शामिल करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य सरकार ने छायंसा स्थित गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के बुनियादी ढांचे को खरीदने का फैसला किया है। यह संस्थान मार्च, 2016 में प्रबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था।

बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की ओर बढ़ते कदम

मनोज प्रभाकर

कोरोना महामारी से निपटने के अथक प्रयासों के चलते प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि राजकीय चिकित्सा सेवा केंद्रों को हर तरह से सुदृढ़ किया जाए ताकि लोगों को उच्च स्तरीय सेवाएं मिल सकें। इस दिशा में बढ़ते कदमों के मद्देनजर कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में उभरकर आ सकता है। राज्य सरकार के प्रयासों के चलते इस क्षेत्र में न केवल आधुनिक चिकित्सा में विकास हो रहा है बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथ व प्राकृतिक चिकित्सा में भी कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। सबसे अहम पहलू यह है कि राजकीय व निजी चिकित्सा संस्थानों की बदौलत हरियाणा ने कोरोना महामारी को काफी हद तक पराजित किया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में आगामी तीन माह में 980 डॉक्टरों की भर्ती करने की घोषणा की है।

मानकों के अनुरूप तैयार होंगे स्वास्थ्य केंद्र

राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप तैयारी की योजना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस बारे में पिछले दिनों चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकमें इस विषय पर जोर दिया और कहा कि इस पर गंभीरता से कार्य शुरू किए जाएं।

उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार ही प्रत्येक जिले में जनसंख्या के आधार पर जितने बेड्स होने चाहिए उतने बेड्स, डॉक्टर व अन्य स्टाफ का प्रबंध किया जाए। प्रदेश के 30 या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की कमी न रहे। इन अस्पतालों में राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सभी बेड को ऑक्सीजन, वेंटीलेटर एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। इसके साथ की अस्पतालों में क्षमता के आधार पर आईसीयू बेड की संख्या निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा सभी चिकित्सकों के लिए रिफ्रैशर कोर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ तथा तकनीकी स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जाएगा।

विज ने कहा कि राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई ई-संजीवनी उपचार की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों में टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा, जोकि एनएबीएल से प्रमाणित होंगी। उन्होंने अस्पतालों के ब्लड बैंकों में ब्लड सेपरेटर मशीने लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि रक्त के विभिन्न अंशों को जरूरत के अनुसार मरीजों को उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न जिला में तैनात चिकित्सकों व अन्य स्टाफ का रेशनलाइजेशन किया जाएगा और आवश्यकतानुसार पदों का सृजन किया जाएगा ताकि सभी अस्पतालों में उचित एवं योग्य स्टॉफ उपलब्ध करवाया जा सके।

आशंकित लहर से निपटने के पर्याप्त इंतजाम

राज्य में वर्तमान में 61,096 आइसोलेशन बेड, बाल रोगियों के लिए 4,040 आइसोलेशन बेड, 14,362 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, पीडियाट्रिक रोगियों के लिए 3,286 ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड, 5,069 आईसीयू बेड और 1535 आईसीयू पीडियाट्रिक बेड, 708 नियोनेटल आईसीयू बेड, 827 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड, 2,058 वेंटिलेटर और 426 बाल चिकित्सा वेंटिलेटर हैं।

राज्य बीपीएल कार्ड धारकों को 2 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजे की नीति बनाई गई है। नीति के तहत 5 लाख रुपये का विशेष अनुग्रह अनुदान भी दिया गया है, जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। कोविड योद्धाओं के परिवारों को 20 लाख रुपये की विशेष अनुकंपा वित्तीय सहायता दी गई।

सभी सरकारी और निजी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार ने 31 पीएसए प्लांट, 4,585 ऑक्सीजन कंसंटेटर, 3400 डी-टाइप और 6873 बी-टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक स्थापित करके अपनी ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ाया है।

ढांचागत विकास की योजनाएं

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (आरओपी) में 1309.52 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है जो वित्त वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 1139.78 करोड़ रुपए की तुलना में बजट स्वीकृति में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि 771 नए उप-केंद्रों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करके उन्हें एचडब्ल्यूसी बनाने की मंजूरी दी गई है और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड एवं नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को जिला अस्पतालों के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, तीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यूपीएचसी कृष्णा गामड़ी, यूपीएचसी चौमा और यूपीएचसी मानेसर के लिए सौर पैनल स्थापित करने, जानवरों के काटने से पीड़ित लोगों के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन/एंटी-रेबीज सीरम का प्रावधान करने और निजी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों 6-18 वर्ष के आरबीएसके के तहत माध्यमिक/तृतीयक उपचार की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य मिशन निदेशक, एनएचएम प्रभजोत सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई नई पहलों में 200 उप केंद्रों एससी का निर्माण, तीन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एमसीएच विंग फरीदाबाद, सोनीपत और पलवल के लिए एमसीएच विंग की स्थापना, 59 मोबाइल मेडिकल यूनिट एमएमयू 47 नए एमएमयूके लिए परिचालन लागत, 56 एडवांस लाइफ सपोर्ट एएलएस एम्बुलेंस 27 नई एएलएस एम्बुलेंस के लिए परिचालन लागत, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भवती महिलाओं की रेफरल प्रणाली में सुधार के लिए मातृ स्वास्थ्य योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए रेफरल लिंकेज के लिए जननी सहायक ऐप शामिल है।

प्रभजोत सिंह के कहा कि इसके अतिरिक्त, जिला अस्पताल सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के तहत 46 अतिरिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 10 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 12 फिजिशियन, 6 बाल रोग विशेषज्ञ, 7 सर्जन, 3 मनोचिकित्सक एवं 8 रेडियोलॉजिस्ट शामिल है।

समर्पित प्रयासों से कोरोना पर विजय

लॉकडाउन के प्रभावी कार्यान्वयन, मॉलीक्यूलर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी, दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना, टेली-मेडिसिन, बीपीएल के लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और चिकित्सा सहायता प्रदान करना, राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में समर्पित हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना आदि के प्रसार के सहयोग से कोविड संक्रमण को रोकने में सहयोग मिला है। टीकाकरण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन एक प्रमुख कारक रहा जिसने वायरस से निपटने में मदद की। प्रदेश में अगस्त मध्य तक लगभग 14 मिलियन खुराक निःशुल्क प्रदान की जा चुकी हैं।

कोविड परीक्षण की मांग को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2020 तक दो कोविड जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। आरटी-पीसीआर परीक्षण क्षमता को प्रतिदिन एक लाख 30 हजार तक बढ़ाने के लिए अब तक 18 नई सरकारी और 21 निजी प्रयोगशालाओं को जोड़ा जा चुका है।

सभी 22 जिलों के अस्पतालों में 24 हजार से अधिक समर्पित कोविड बेड उपलब्ध कराए गए हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और बाई-पैप सेवाओं के साथ आईसीयू बेड स्थापित किए गए थे तथा सिविल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों और निजी/कॉर्पोरेट अस्पतालों में क्षमता बढ़ाई गई।

450 मोबाइल स्वास्थ्य टीमों की सुविधा दूर-दराज के क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराई गईं। लॉकडाउन के दौरान मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं भी स्थापित की गईं।

रोगियों को होम आइसोलेशन किट भी मुफ्त प्रदान की गई, जिसमें सूचना के लिए पुस्तिका, पल्स-ऑक्सीमीटर, स्टीमर, डिजिटल थर्मामीटर, दवाएं और आयुष प्रतिरक्षा बूस्टर शामिल थे।

लापरवाही की जांच के लिए कमेटी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की। महामारी के दौरान व्यवस्था में लापरवाही करने वालों के खिलाफ जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जहां-जहां लापरवाही मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र के दौरान बताया कि हरियाणा के अस्पतालों में लगभग 13,000 लोगों की कोविड के कारण मृत्यु हुई। इनमें से लगभग 9,500 हरियाणा के रहने वाले थे, जबकि लगभग 3,500 हरियाणा के बाहर के कोविड मरीजों की मृत्यु हुई। हरियाणा में लगभग 4,000 निजी अस्पताल हैं।

उन्होंने कहा कि हिसार, रेवाड़ी और गुरुग्राम में कुछ अस्पतालों में लापरवाही की बात सामने आई थी। इन तीनों स्थानों पर लापरवाही के मामलों की मजिस्ट्रेट जांच कराई गई है। दो स्थानों की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत हुई है। हिसार के मामले की जांच रिपोर्ट में अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आई है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि निजी स्कूलों को स्थाई मान्यता देने के लिए मानदंडों में ढील दी गई है। स्कूलों को स्थाई मान्यता देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से पोर्टल बनाया गया है, जहां आवेदन किया जा सकता है।

सीएम विंडो से व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास सीधी शिकायतें पहुंचा रहे हैं। मुख्यालय स्तर पर भी इनकी नियमित निगरानी की जाती है। शिकायतकर्ता को मोबाइल पर शिकायत की सुनवाई की सूचना भी दी जाती है।

सरकार को जमीन बेच सकेंगे किसान

यदि किसी किसान को मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ जाए तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने उन्हें एक विकल्प उपलब्ध करवाया है। इसके तहत, किसान पहले सरकार को संभावित खरीददार के रूप में अपना प्रस्ताव दे सकता है। इसके साथ ही किसान राज्य सरकार को किसी विशेष स्थान पर विकास परियोजना के लिए भूमि का चयन करने का परामर्श भी दे सकते हैं। इसके लिए सरकारी विभागों, बोर्डों एवं निगमों के लिए भूमि बैंक सृजित करने और उनके निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नीति तैयार की गई है।

इस नीति को 'बोर्डों एवं निगमों सहित सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि बैंक सृजित करने और विकास परियोजनाओं के लिए उनका निपटान नीति' कहा जाएगा।

आवश्यक सेवाओं के लिए उपयोग

इस नीति के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तीन समितियां नामतः भूमि एवं दर जांच समिति, भूमि बैंक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त भूमि बैंक समिति का गठन किया जाएगा। यह देखा गया है कि कई बार भूमि मालिकों, विशेष रूप से जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें बाज़ार में मंदी या महामारी के कारण या बाज़ार में बिचौलियों के दबाव या विभिन्न कारणों से मज़बूरन अपनी ज़मीन की बिक्री करनी पड़ती है। उक्त वर्णित कारणों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न विभागों को दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जलघरों, बिजली सब-स्टेशनों, कॉलेज और उच्च शिक्षा के अन्य विशिष्ट संस्थानों, जिनमें विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पताल एवं पॉलिटेक्निक आदि शामिल हैं, जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों द्वारा भूमि की मज़बूरन बिक्री को रोकने के लिए किसानों के पास हरियाणा में अपनी भूमि के लिए निदेशक भूमि अभिलेख के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने का विकल्प होगा। इसके लिए उन्हें मोलभाव करने लायक मूल्य सहित भूमि का पूरा विवरण देना होगा। इसके अलावा, राजस्व विभाग इस भूमि को सरकार के सभी विभागों और बोर्डों एवं निगमों की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए उक्त भूमि बैंक में रखेगा और संबंधित नियमों/स्थायी आदेशों/नीतियों के अनुसार उनकी कीमत, यदि कोई हो, के अनुसार उन्हें हस्तांतरित करेगा।

किसानों के लिए अहम जानकारी

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के गांधी भवन में नाबार्ड एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित एबिक पिछले दो वर्षों से बेरोज़गारों के लिए रोजगार सृजन करने का कार्य कर रहा है।

वर्ष 2019 से संचालित में इस केंद्र में पिछले वर्ष 17 लोगों ने आवेदन किया था जिसमें 8 महिलाएं चयनित हुई थी। अब तक इस केंद्र से 27 आवेदकों की अनुदान राशि स्वीकृत हुई थी। केंद्र में 10 लोगों की टीम सफलतापूर्वक कार्य करती है। प्रशिक्षण के लिए चयनित होने के बाद उन्हें केंद्र 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्र अब तक दोनो वर्षों के चयनित व्यक्तियों को तीन करोड़ 15 लाख की राशि प्रदान कर चुका है। केंद्र में प्रशिक्षण पाने वालों को किसी प्रकार की डिग्री या डिप्लोमा की बंदिश नहीं हैं। अनपढ़ व्यक्ति भी प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। यह अनुदान राशि एक प्रक्रिया के तहत कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है। इसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।

केंद्र ने इसकी शुरुआत युवाओं ,किसानों एवं उन उद्यमियों के लिए विशेष तौर पर की हुई है। जो नया करना चाहते हैं व अपने क्षेत्र में पहले से स्थापित है। केंद्र इस दिशा में मार्केटिंग, नेटवर्किंग,लाइसेंसिंग ट्रेडमार्क व पेटेंट तकनीक व फंडिंग संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में आवेदन करने वालों का मार्गदर्शन करके उन्हें से यहां संचालित दो कार्यक्रमों पहल व सफल का मार्गदर्शन करता है। केंद्र से संचालित पहल प्रोग्राम के लिए 5 लाख की राशि व सफल प्रोग्राम के लिए 25 लाख की राशि निर्धारित की गई है।

आवेदक को आवेदन से पहले इन बातों का ध्यान रखना होता है। केंद्र द्वारा आवेदन की प्रक्रिया निःशुल्क की हुई है। आवेदन करने वाला प्रदेश या फिर निकटवर्ती राज्य का होना चाहिए। अगर वह बाहर का है तो उसे हरियाणा में आकर अपना व्यवसाय स्थापित करना होगा। आवेदन करने वाले का मुख्य आइडिया एग्री बॉयोटेक, बागवानी, जैविक खेती, पशुपालन मत्स्य पालन, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि अभियांत्रिकी, खेती मशीनीकरण के अलावा कटाई व कटाई के बाद की प्रक्रिया खाद्य प्रक्रिया एवं मूल्य संवर्धन कृषि में कृत्रिम बुद्धिमता इत्यादि पर अन्वेषण किया हो व अपने व्यवसाय को स्थापित कर चुका हो का विशेष ध्यान रखना होगा।

प्रबंधक विक्रम संधु के अनुसार कृषि के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पेटेंट, मूल्य संवर्धन, सर्विसिंग, पैकजिंग व ब्राडिंग करके व्यापार को आगे बढ़ाने की संभावनाओं, युवा व किसानों के कृषि व कृषि से संबंधित उनमें विद्यमान कौशल व उनके नवाचारों को निखारने के अलावा अपना व्यवसाय स्थापित करने में आने वाली प्रारंभिक दिक्कतों, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रिकॉर्ड, उसकी जरूरतें, तकनीकी आवश्यकता, लाइसेंसिंग, फंडिंग, विपणन, कानूनी दिक्कत आदि को लेकर पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाता है।

सब्ज़ी की खेती से सालभर मुनाफ़ा

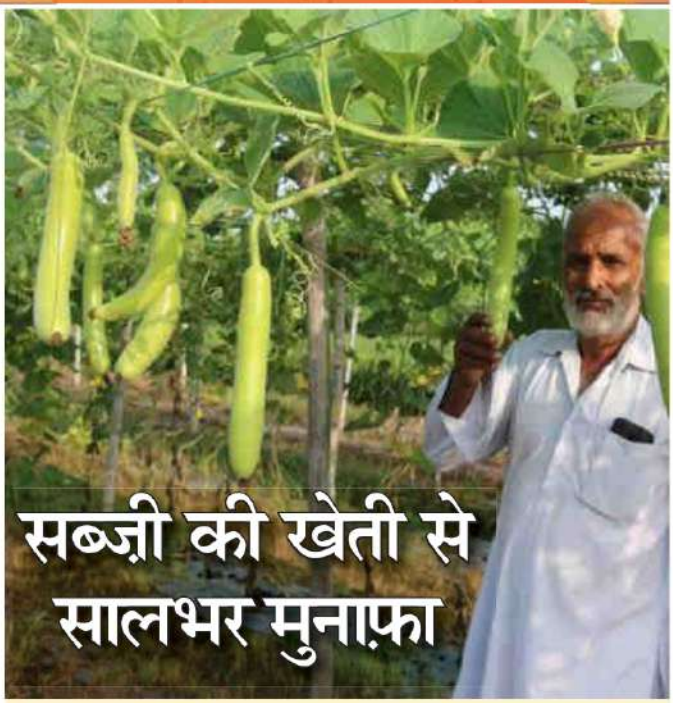

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान की ओर से मौसमी सब्जियों की खेती विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ।

संस्थान के सह-निदेशक (प्रशिक्षण) डॉ. अशोक गोदारा ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सब्जियों की उचित समय पर बेहतर तरीके से उत्पादन करने के बारे में जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को मौसमी सब्जियों की सालभर खेती करने की जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि किसान सब्जियों की खेती से सालभर मुनाफा हासिल अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवक-युवतियां संस्थान से प्रशिक्षण हासिल कर स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।

घरों पर सब्जी उगाने का प्रयास करें

डॉ. हरदीप सिंह ने बताया कि भूमि व खारे पानी में सुधार कर सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इसके लिए मिट्टी-पानी की जांच करवानी चाहिए। परिवार की आवश्यकता अनुसार घर पर ही ताजी एवं स्वादिष्ट सब्जियां सालभर उपलब्ध रहती हैं जो बाजार की तुलना में सस्ती व गुणवत्ता वाली होती हैं। उन्होंने बताया कि किसान घर पर ही किचन गार्डन के माध्यम से भी घर के कूड़े का कम्पोस्ट खाद बना कर प्रयोग किया जा सकता है।

डॉ. दविंद्र सिंह ने नर्सरी तकनीक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रो-ट्रे नर्सरी में तैयार होने वाली सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, लौकी, कद्दू, करेला, तरबूज, खरबजूजा, ककड़ी, पत्ता गोभी, फूलगोभी आदि के बारे में बताया। डॉ. टोडरमल ने सब्जियों की फसलों में खरपतवार नियंत्रण व सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए रसायनों का ही प्रयोग करना चाहिए।

डॉ. निर्मल ने सब्जियों की काश्त का आर्थिक विश्लेषण करते हुए बताया कि इससे अन्य फसलों की तुलना में अधिक आय होती है। उन्होंने कहा कि दिनों-दिन जोत कम होती जा रही है जिससे आय में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में किसान संयुक्त कृषि प्रणाली को अपनाकर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं।

पशुपालन के जरिए रोजगार के अवसर

राज्य सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं पशुपालकों के लिए संचालित की हैं। पशुपालक 4 से 10 पशुओं की व 20 से 50 पशुओं की यूनिट स्थापित कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से इन योजनाओं के तहत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

योजना के लिए आवेदन करने वाला हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन यदि आवेदन की पशुपालन संबंधी क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण लिया हुआ है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के समय प्रार्थी को अपना आधार कार्ड ,पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र के अलावा बैंक खाते का कैंसिल चेक तथा बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक इसे सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

योजना के तहत अगले दो महीने तक सरल पोर्टल पर पशुपालक आवेदन कर सकते है। प्रदेश के 22 जिलों में 500 पशुपालकों को इन योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा के संयुक्त निदेशक डा रांगी ने बताया कि सरकार की ओर से पशुपालन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हुई है। सरकार का उद्देश्य पशुपालन व स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

सोनीपत के सेरसा गांव में ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्किट को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसमें वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज आदि की सुविधाएं होगी।

सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर रेवाड़ी जिले को पहला स्थान मिला है। रेवाड़ी ने पूरे प्रदेश में 9.6 का स्कोर हासिल किया है।

'वर्मी कम्पोस्ट' से स्वयंरोज़गार

संगीता शर्मा

महेंद्रगढ़ जिला कनीना खंड से गांव धनोदा के युवा दीपक सिंह वर्मी कम्पोस्ट (केंचुआ खाद) यूनिट लगाकर अच्छा ख़ासा कमा रहे हैं। एमएससी, बीएड (गणित) प्राइवेट स्कूल में गणित के टीजीटी शिक्षक भी हैं। उन्होंने बताया कि चार एकड़ पुश्तैनी ज़मीन है जिसमें बाजरा, गेहूं, सरसों, कपास की खेती करते हैं, लेकिन अब वह बागवानी व सब्ज़ियों की खेती पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।

उन्होंने दो महीने पहले ही 'नेचर ग्रीन आर्गेनिक' नाम से यू-ट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसके माध्यम से वर्मी कपोस्ट के बैड तैयार करने की तकनीक, पानी का प्रयोग और अन्य जैविक खाद से संबंधित सारी जानकारी विस्तार से प्रसारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त फेसबुक में 'आर्गेनिक' नाम से पेज भी बनाया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया से मार्केटिंग में आसानी हो जाती है और उनका वर्मी कम्पोस्ट भी बिक जाता है। उन्होंने बताया कि इच्छुक लोगों को अपने खेत में आमंत्रित करके वर्मी कंपोस्ट के बैड का निरीक्षण करवाता हूं और साथ ही निःशुल्क प्रशिक्षण भी देता हूं।

उन्होंने वर्ष 2019 में पहले मेरठ और बाद में कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने का प्रशिक्षण लिया। डॉ. रमेश यादव की देखरेख में अपनी प्रतिभा को निखारा। जब कोई भी कम्पोस्ट से संबंधित दिक्कत आती तो उनके मार्गदर्शन व उचित सलाह से सुधार हो जाता। उन्होंने बताया कि तीन-चार बैड से वर्मी कम्पोस्ट यूनिट बनाने

की शुरुआत की थी और इस समय 50-55 बैड बनाए हैं।

खाद बनाने का तरीका

उन्होंने बताया कि तीन मैथेड से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करते हैं। अपर पिट मैथेड में ज़मीन को दो फीट गहरा खोदकर गोबर व केंचुआ डालकर वर्मी कम्पोस्ट तैयार करते हैं या फिर बनाया दो फीट ऊंचाई वाला बैड बाजार से व ऑनलाइन खरीदकर उसमें खाद व केंचुआ डालकर वर्मी कम्पोस्ट तैयार करते हैं। डीप पिट मैथेड में जहां समतल जगह उपलब्ध हो वहां दो फीट गहराई में वर्मी कम्पोस्ट तैयार करते हैं। तीसरा विडड्रो तकनीक से वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। पहले भूमि को समतल किया जाता है। जिसमें नौ फीट चौड़ा व 30 फीट लंबा कागज बिछाकर उसे चार-चार फीट चौड़े दो हिस्से में बांट दिया जाता है। फिर गोबर को गीला करके फैला देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर केंचुआ डाला जाता है। अंत में बाजरा की पूली या धान की पराली से उसे ढक देते हैं। बाद में मौसम के अनुसार समय-समय पर पानी देते हैं। अधिक गर्मी में सुबह 7-9 और शाम को 5 बजे के बाद पानी देते हैं। सर्दियों में 10-15 में पानी देना पड़ता है। सही तापमान व नमी होने पर

40-45 दिन में दो-तीन इंच की परत वाली जैविक खाद तैयार हो जाती है। फिर उसे छानकर थैले में भरा जाता है। एक बैड से तीन बार खाद तैयार होती है और नीचे केंचुएं ही बचते हैं।15 क्विंटल गोबरसे 5-6 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार हो जाती है।

उन्होंने बताया कि आरंभ 60,000 से 70,000 रुपए का खर्चा आया और मेरठ से 120 किलो केंचुए 350 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदकर लाए। उन्होंने बताया कि इसमें खर्चा एक बार आता है और इसके बाद इससे मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा मिलता है। गोबर को गौशाला से 1,200 रुपए ट्राली यानी 40 क्विंटल खरीदते हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो वर्मी कम्पोस्ट 45 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन बारिश व नमी के कारण 60-75 दिन लगते हैं।

जैविक खाद की बढ़ती मांग

उन्होंने बताया कि वह वर्मी कम्पोस्ट को 200 से 250 रुपए प्रति किलो की दर से बेचते हैं और स्थानीय किसान उनसे खरीदकर ले जाते हैं। उनका कहना है कि कोरोना के बाद लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग हो गए हैं और जैविक उत्पाद खाना पसंद कर रहे हैं। इसके चलते किसानों को जैविक खेती करनी शुरू कर दी है।

उन्होंने एक एकड़ में गेहूं की दो किस्में ब्लैक वीट और बंसी गोल्ड किस्म की पैदावार की। इसमें केंचुआ खाद का प्रयोग किया और उच्चत्तम व गुणवत्ता वाली गेहूं किस्म की पैदावार हुई। उन्होंने बताया कि इस गेहूं को घर के प्रयोग के लिए उगाया था और अपनी फसल को लेकर बहुत खुश हैं।

गाजर घास का उन्मूलन आवश्यक

गाजर घास न केवल फसलों के लिए बल्कि पर्यावरण के साथ-साथ इंसानों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिक लगातार प्रदेश भर में गाजर घास के प्रति किसानों को जागरूक कर रहे हैं।

इसी कड़ी में विश्वविद्यालय के अनुसंधान क्षेत्र में गाजर घास जागरूकता सप्ताह व उन्मूलन अभियान चलाया गया। इस दौरान अनुसंधान निदेशक डॉ. एस.के. सहरावत ने कहा कि गाजर घास से फसल की पैदावार में चालीस प्रतिशत तक कमी हो सकती है। इसलिए समय रहते समन्वित प्रबंधन से इस खरपतवार पर नियंत्रण किया जा सकता है। कार्यक्रम का आयोजन सस्य विज्ञान विभाग द्वारा जबलपुर के खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पौधे का प्रवेश हमारे देश में अमेरिका से आयात होने वाले गेहूं के साथ साल 1955 में हुआ था। अब यह पौधा संभवत देश के हर हिस्से में मौजूद है और लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैल चुका है। जब यह एक स्थान पर जम जाती है, तो अपने आस-पास किसी अन्य पौधे को जमने नहीं देती है जिसके कारण अनेकों महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों और चरागाहों के नष्ट हो जाने की सम्भावना पैदा हो गई है। इस घास के कारण मनुष्यों के अलावा पशुओं में भी बीमारी के लक्षण आने लगे हैं। गाजर घास के एक पौधे से लगभग 10,000 से 20,000 बीज पैदा होते हैं, जो ज़मीन में पुनः नमीं पाकर

अंकुरित हो जाते हैं।

वैज्ञानिक डॉ. सतबीर सिंह पूनिया ने बताया कि इस घास के निवारण हेतु कुछ शाकनाशियों के प्रयोग जैसे एट्राजिन /मेट्रिब्यूजिन (0.5 प्रतिशत) व ग्लाइफोसेट (1-1.5 प्रतिशत) का प्रयोग करके इस खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है।

-संवाद ब्यूरो

अनाज साफ करता पावर फैन

राजेंद्र पूनिया हिसार के गांव सातरोड़ कलां निवासी राजेंद्र पूनिया ने अनाज की सफाई के लिए सुपर पावर फैन तैयार किया है। यह फैन एक घंटे में 80 क्विंटल धान, गेहूं, सरसों, बाजरे की सफाई का कार्य आसानी से कर देता है जबकी मार्केट के अन्य पंखे मात्र 40 क्विंटल के आस-पास ही कर पाते हैं।

उपकरण की मांग को देखते हुए उन्होंने फैक्ट्री लगाने का मन बनाया तो पैसे की कमी आड़े आई। उन्होंने इस स्थिति में एचडीएफसी से 12 लाख रुपए का ऋण लिया व हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार स्थित एबिक से 2 महीने का प्रशिक्षण लिया।

वे कहते है, सुपर पावर फैन चारों तरफ से सुरक्षित है। इससे किसी भी प्रकार का कचरा इसके माध्यम से नहीं जाता। पूरा अनाज साफ हो जाता है। इसमें दो चेंबर काम करते हैं पहले चेंबर में अनाज साफ होकर ट्राली में लोड हो जाता है व दूसरे चेंबर में कुछ अनाज एलिवेटर में चला जाता है यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसे रीसाइकिलेबल हो जाता है बार-बार घुमाने से दाने में चमक आती है व इसे क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। बिजली की खपत भी बहुत कम होती है।

जल प्रबंधन अवार्ड

जल प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही अनेक योजनाओं एवं उसके परिणामों को देखते हुए हरियाणा सरकार को 'द एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन' द्वारा प्लेटिनम कैटेगरी के तहत ग्लोबल इनोवेशन इन वॉटर टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया है।

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सतबीर कादियान ने बताया कि प्रदेश का सिंचाई विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है और उनके दिशा-निर्देशों के तहत विभाग विकास के निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि जल प्रबंधन को लेकर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया गया है, साथ ही जल प्रबंधन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। राज्य के लिफ्ट कैनाल सिस्टम को लगातार सराहना मिल रही है।

कादियान ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने यह सम्मान एक वर्चुअल कार्यक्रम में हरियाणा को दिया। उन्होंने बताया कि जल प्रबंधन की शानदार योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने की वजह से हरियाणा को यह अवार्ड मिला है।

निजी क्षेत्र में युवाओं को रोज़गार के प्रदान करने के लिए प्रति वर्ष 200 रोज़गार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिले में जिला रोज़गार कार्यालय द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक रोज़गार मेला आयोजित करना अनिवार्य है।

प्रदेश में भूमि बैंक बनाया जाएगा तथा सभी पटवारियों व कानूनगो को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि योजना को प्रभावी रूप से चलाया जा सके और भू-मालिकों को भी उनकी ज़मीन की सही जानकारी मिल सके।

ओलंपियनों के सम्मान से ग्रामीण अभिभूत

टोक्यो ओलंपिक से लौटे प्रदेश के खिलाड़ियों के सम्मान में जगह-जगह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के पैतृक गांवों में विशेष सम्मान समारोह हुए जिनमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेल मंत्री संदीप सिंह व अन्य नेतागण व अधिकारियों ने शिरकत की।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्रामीणों द्वारा आयोजित नाहरी और कुराड़ के ओलंपिक पदक विजेताओं के अभिनंदन समारोह में मुख्यातिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों रवि दहिया व सुमित को आशीर्वाद देते हुए गांवों के विकास को नई दिशा प्रदान की। इस दौरान नाहरी के लाडले रवि दहिया ने और कुराड़ के प्यारे सुमित ने अपने गांवों की ओर से मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपे, जिनमें शामिल सभी मांगों को मुख्यमंत्री ने तुरंत स्वीकृति प्रदान की। ग्राम पंचायत की ओर से मिली कुछ मांगों को तो

उन्होंने गांव में पहुंचने से पहले ही पूरा करवा दिया।

मुख्यमंत्री पहले नाहरी पहुंचे जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। नाहरी के इतिहास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं अपितु क्रांतिकारियों का गांव है। विश्व युद्ध में गांव के 229 सैनिकों ने हिस्सा लिया था जिनमें से 31 सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की थी। नाहरी के ही खुशाल सिंह दहिया ने सिख गुरु तेगबहादुर के शीश के सम्मान के लिए अपना सिर कलम करवा लिया था, जिसकी स्मृति बड़खालसा में है। शिक्षा में भी नाहरी का मुकाबला नहीं जहां 38 एमबीबीएस चिकित्सक हुए हैं। गांव ने इतिहास रचा है जिसके आगे मैं नतमस्तक हूं।

इंडोर स्टेडियम के साथ मॉडल संस्कृति स्कूल की सौगात

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रवि दहिया को कुश्ती की नई पौध तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नाहरी में इंडोर स्टेडियम स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने गांव को राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल का तोहफा भी दिया। गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के लिए 'म्हारा गांव-जगमग गांव' में नाहरी को शामिल करवाने के लिए ग्रामीणों की सहमति ली, जिसके लिए उन्होंने 660 लोगों के लंबित 50 लाख रुपए के बिजली बिलों में से 20 लाख रुपए की पैनल्टी माफ की। शेष बिल की अदायगी के लिए भी उन्होंने किश्त की सुविधा दी।

कुराड़ में हॉकी नर्सरी

कुराड़ के विकास को नई बुलंदी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव में 6-ए साइड का हॉकी मैदान स्थापित करने की घोषणा करते हुए सुमित का आह्वान किया कि वे यहां हॉकी खिलाड़ियों को गुरूमंत्र दें। गांव में हॉकी नर्सरी के साथ कोच की नियुक्ति की भी सौगात दी। गांव के स्कूल के कमरों के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल की हर जरूरत पूरी करेंगे। गांव के दो तालाबों के गंदे पानी की निकासी के निर्देश देते हुए खेतों वाले जोहड़ की रिटर्निंग वॉल व जाहरी रोड के चौड़ीकरण व मरम्मत के निर्देश दिए। ग्रामीणों की सुविधा के लिए कुराड़ को पुरखास पीएचसी से निकालकर मुरथल पीएचसी के साथ जोड़ने की घोषणा की।

दृढ़ निश्चय से हासिल की जीत

टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा को भगवान तिरूपति बालाजी की मूर्ति व शॉल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने नीरज चोपड़ा को देसी घी का चूरमा खिला कर सदैव आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया।

दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं व अपनी ओर से आशीर्वाद देते हुए कहा कि और अधिक दृढ़ निश्चय तथा संकल्प के साथ खेल की तैयारी जारी रखें तो वे निश्चित रूप से अपने जैवलिन थ्रो में रखे गए 90 मीटर के लक्ष्य को पार करेंगे। ज्ञात रहे कि 90 मीटर थ्रो के इसी लक्ष्य को साधने के लिए नीरज चोपड़ा ने अभी से कार्य शुरू कर दिया है।

-संवाद ब्यूरो

स्कूली पाठ्यक्रम में बहेगी 'सरस्वती की धारा'

प्राचीनतम पवित्र नदी सरस्वती के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की योजना है। यह पाठ्यक्रम छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के लिए तैयार किया जाएगा। इसे तैयार करने के लिए सरस्वती सिलेबस कमेटी का गठन किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डा. प्रीतम सिंह को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 11 सदस्यीय कमेटी को 15 सितंबर 2021 तक रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है।

सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा और शिक्षा मंत्री कंवरपाल के निर्देशानुसार पांच हजार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी पवित्र सरस्वती नदी के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए।

कमेटी में जिओलॉजी विभाग की रिसर्च ऑफिसर डा. दीपा मेहता को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ-साथ इस कमेटी में विद्या भारती शिक्षण संस्थान के निदेशक डा. रामेन्द्र सिंह, सीईआरएसआर कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर डा. एआर चौधरी, पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर प्रियातोष, जिओग्राफी विभाग कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर डा. केतकी राणा, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशीष तिवान, एससीईआरटी गुरुग्राम के रिप्रिजेंटिव, स्कूल लैक्चरर डा. रेविका हुड्डा, जीएमएसएसएसएस इस्माईलाबाद के प्रोफेसर डा. दिनेश यादव, जीएचएस जलबेहड़ा की जिओग्राफी पीजीटी प्रतिका, एचएसएचडीबी के जिओलॉजी की रिसर्च अधिकारी डा. दीपा को शामिल किया गया है।

शिक्षित होने के साथ संस्कारवान होना जरुरी

उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि भारत की सबसे प्राचीनतम नदी सरस्वती का एक अलग ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस नदी के तटों के किनारे ही भारतीय संस्कृति पली, बढ़ी और विकसित हुई है। इस नदी के किनारे अनेकों ऋषि मुनियों ने तप किया। देश को ज्ञान का प्रकाश देने वाली इस नदी को अब पाठ्यक्रम में शामिल करके भारत की इस प्राचीन संस्कृति को फिर से जीवंत किया जाएगा। जब देश के बच्चे अपनी विरासत और धरोहर के बारे में जानेंगे तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारवान बनाया जा सकेगा।

बीपीएल परिवारों को आर्थिक मदद

हरियाणा के अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉ बनवारी लाल ने बताया कि दिनांक 27.02.2021 को संत शिरोमणी गुरू रविदास जी की जयन्ती समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि डा. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी परिवारों को दिया जाएगा और आर्थिक सहायता की राशि 50,000 / - रुपये से बढ़ाकर 80,000 / - रुपये कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कुल 7,76,771 परिवार हैं। इनमें से कुल 4,02,305 परिवार अनुसूचित जाति और 3,74,466 परिवार समाज के अन्य वर्गों से सम्बन्धित हैं। यदि इन 7,76,771 परिवारों में से 2.5 प्रतिशत परिवार इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए कुल 15,536.00 लाख रूपए की आवश्यकता होगी। वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में इस स्कीम में कुल 5000 लाख रूपए की व्यवस्था की गई है। अतः उपरोक्त व्यवस्था करने के लिए कुल 10,536 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी।

कोविड संक्रमण कम होने से चौथी व पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए माता पिता एवं अभिभावकों की पूर्व अनुमति अनिवार्य रहेगी।

हरियाणा साहित्य अकादमी में लेखक संतराम देशवाल द्वारा रचित पुस्तक इक्कीसवीं सदी के ललित निबंध व लोक साहित्य में कड़का विद्या व कवियत्री राजकला देशवाल की पुस्तक उजली राहें का लोकार्पण हुआ।

आत्मनिर्भर होती महिलाएं

संगीता शर्मा

प्रदेश में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो रहा है। महिलाएं एकजुट होकर क्रिएटिव काम करती हैं और मार्केटिंग करके मुनाफ़ा कमाती है। साथ ही थोड़े-थोड़े रुपए एकत्रित करके आपस में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गठित महिलाओं के 'स्वयं सहायता समूह' को और अधिक सशक्त करने के लिए उनको करीब 46.16 करोड़ रुपए के ऋण व अन्य आर्थिक सहायता दी गई। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय-फंड जारी किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद' कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली से 'स्वयं सहायता समूहों' में अहम कार्य करने वाली देशभर की सशक्त महिलाओं से वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बात की। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे।

स्वयं सहायता समूह की दुकाने

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर कार्य करने वाले 'स्वयं सहायता समूहों' की महिलाओं को उनके कार्य से संबंधित बड़े प्रोजेक्ट्स का विजिट करवाया जाएगा ताकि वे अपने बिजनेस में वृद्धि कर सकें। राज्य सरकार प्रयास करेगी कि प्रदेश के हर सेक्रेटेरिएट में स्वयं सहायता समूह की दो दुकानें खोली जाएं जिनमें एक खाने के समान की तथा दूसरी अन्य उत्पादों की हो। इससे जहां इन समूहों की महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा वहीं लोकल-ब्रांड को प्रोत्साहन मिलेगा।

हस्तशिल्पियों की प्रदर्शनी का निरीक्षण

पिंजौर के यादविन्द्रा गार्डन में 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' के स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता से आयोजित तीज महोत्सव के दौरान उपमुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के हस्तशिल्पियों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उसके बाद स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित किए गए। इनके अलावा सर्वश्रेष्ठ स्टॉल, सर्वश्रेष्ठ जिला व सर्वश्रेष्ठ समूह को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने गुरुग्राम के उस स्वयं सहायता समूह की विशेष तौर पर सराहना की जिसने 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया' से पंजीकरण करवाकर अपने उत्पादों को बाजार में उतारा है।

'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन'

- 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' द्वारा प्रदेश के 142 खंडों में 46,163 'स्वयं सहायता समूहों' के माध्यम से 4,91,120 परिवार जुड़े हुए हैं।
- मिशन द्वारा 35,310 'स्वयं सहायता समूहों' को वित्तीय सहायता के रूप में 36.53 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई।

अब महिलाएं चूल्हा-चौका, कढ़ाई-बुनाई तक सीमित नही हैं, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' ने अभी तक 4.50 लाख महिलाओं को सशक्त किया है और भविष्य में इन समूहों को कौशलयुक्त करने के लिए जो भी राज्य सरकार की सहायता की जरूरत होगी, वह पूरी तरह से उपलब्ध करवाई जाएगी। मिशन द्वारा राज्य की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को करीब 26.16 करोड़ रुपए का ऋण विभिन्न बैंकों से दिलवाया गया ताकि वे स्वरोजगार कर सकें। इसके अलावा महिलाओं को 4.71 करोड़ रुपए के वाहन-ऋण भी वितरित किए गए हैं ताकि वे अपने वाहन से उनके द्वारा तैयार उत्पादों को दूसरी जगह ले जाकर बेच सकें।

दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

- मिशन द्वारा 2,916 ग्राम संगठन व 130 क्लस्टर लेवल फैडरेशन के माध्यम से 37,444 'स्वयं सहायता समूहों' को सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 361.66 करोड़ रुपए की धनराशि महिलाओं को उपलब्ध करवाई गई।
- 'स्वयं सहायता समूहों' की महिलाओं को जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 20.38 करोड़ रुपए से ज़्यादा के वित्तीय-फंड जारी किए गए हैं।

बीमा का प्रीमियम भरेगी सरकार

हरियाणा सरकार ने 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रक्षा बंधन के पर्व पर तोहफ़ा देते हुए इन महिलाओं का 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' का प्रीमियम 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' से भरने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय से करीब 3.25 लाख महिलाओं को लाभ होगा।

कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। राज्य में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी 4 लाख 91 हजार 200 महिलाओं में से लगभग एक लाख 64 हजार महिलाओं ने तो 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' से खुद को कवर कर लिया है परंतु लगभग 3 लाख 25 हजार महिलाएं अब भी ऐसी बची हुई हैं जो महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के चलते उक्त योजना का लाभ नहीं उठा सकी। उक्त महिलाओं का लगभग 40 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत किया जाएगा।

स्वयं सहायता समूहों' को वित्तीय अनुदान राशि	
जिला	अनुदान राशि (लाख रुपए में)
अंबाला	154.65
भिवानी	118.60
चरखी दादरी	156.55 2
फरीदाबाद	56.00
फतेहाबाद	85.30
गुरुग्राम	91.10
हिसार	28.77
झज्जर	72.15
जींद	216.95
कैथल	41.90
करनाल	74.00
कुरुक्षेत्र	69.10
महेंद्रगढ़	59.10
नूह	121.40
पलवल	73.10
पंचकूला	74.10
पानीपत	62.45
रेवाड़ी	91.35
रोहतक	45.10
सिरसा	115.55
सोनीपत	40.00
यमुनानगर	191.35

महिला सशक्तिकरण के लिए 'सखी'

हिसार की 'सखी' चैरिटेबल ट्रस्ट गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाकर अच्छा इंसान में मदद कर रही है ताकि वह कूड़ा बीनने वाले कार्य से दूर होकर अच्छी नौकरी पा सकें। पेशे से वकील व हिसार के 'सखी' चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन भावना शर्मा बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। उन्होंने कोरोना काल में लोगों को निःशुल्क मास्क, खाद्य सामग्री व पका हुआ भोजन वितरित किया। वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी करती हैं।

सखी फाउंडेशन से 250 से 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें हिसार व फतेहाबाद के गांवों की महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाएं गांव-गांव में जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वे हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं। इसके साथ जल संरक्षण व स्वच्छता का पाठ पढ़ाती हैं। उन्होंने बताया कि गांव में महिलाएं गाय-भैंस को नहलाने, घर-आंगन और सड़क धोने में काफ़ी पानी व्यर्थ करती हैं और उनकी 'सखी' महिलाएं उन्हें पानी की बचत के बारे में बताती हैं। महिलाएं मिलकर पौधारोपण भी करती हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। इस समय उन्होंने पीपल, शीशम, नीम व अन्य फूलों के पौधे भी रोपित किए हैं।

उनके ट्रस्ट के सदस्य बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवाते हैं और उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसी बच्चियां जो खेलना चाहती है लेकिन आर्थिक तंगी के कारण खेल नहीं पाती उन्हें खेल सामग्री व अन्य सुविधाएं देकर मदद करती हैं।

भावना ने बताया कि वह गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक करती हैं और जरूरत पड़ने पर उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाती है। महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देने के लिए इंतजाम कर रही हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। भावना कई महिलाओं को 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' का लाभ पहुंचा चुकी हैं। भावना व उनके समूह के सदस्य गांव-गांव जाकर लड़कियों को सेक्स एजुकेशन के प्रति जागरूक करेंगी ताकि उनके प्रति कुछ गलत हो रहा हो तो वह इसकी शिकायत कर सकें। भावना स्कूलों व कॉलेजों में जाकर भी लड़कियों को लैक्चर के माध्यम से जागरूक करती है। भावना ने बताया कि उसने हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के अच्छे कार्य के लिए दिए जा रहे है पुरस्कार के लिए आवेदन करना है ताकि उनके कार्य को पहचान मिल सकें। 'सखी' चैरिटेबल ट्रस्ट हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है। लोग आपसी सहयोग व वित्तीय मदद से यह ट्रस्ट चला रहे हैं।

-संवाद ब्यूरो

उत्कृष्ट प्राध्यापक ममता पालीवाल

भिवानी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गणित प्रवक्ता के पद पर कार्यरत ममता पालीवाल को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने एमएससी बीएड तक की पढ़ाई की है। वर्ष 2005 में स्नातक की पढ़ाई फतेहचंद महिला महाविद्यालय, हिसार से की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हैप्पी पब्लिक स्कूल, भिवानी से शिक्षक के रूप में करियर की शुरुआत की। वर्ष 2011 में उन्होंने राजकीय कन्या हाई स्कूल में गणित अध्यापक के पद पर चयन हुआ तथा वर्ष 2016 में पदोन्नति हुई।

हरियाणा कला परिषद् के निदेशक संजय भसीन को दिल्ली में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर कॉउंसिल द्वारा भारत श्री अवार्ड 2021 से नवाजा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संजय भसीन को सम्मानित किया गया।

18 व 19 अगस्त को प्रदेश के राशन डिपुओं पर अन्नपूर्णा उत्सव मनाया गया। इन दिनों एक करोड़ 22 लाख लोगों को विशेष थैली में निःशुल्क अन्न वितरण किया गया।

सुल्तानपुर और भिंडावास को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

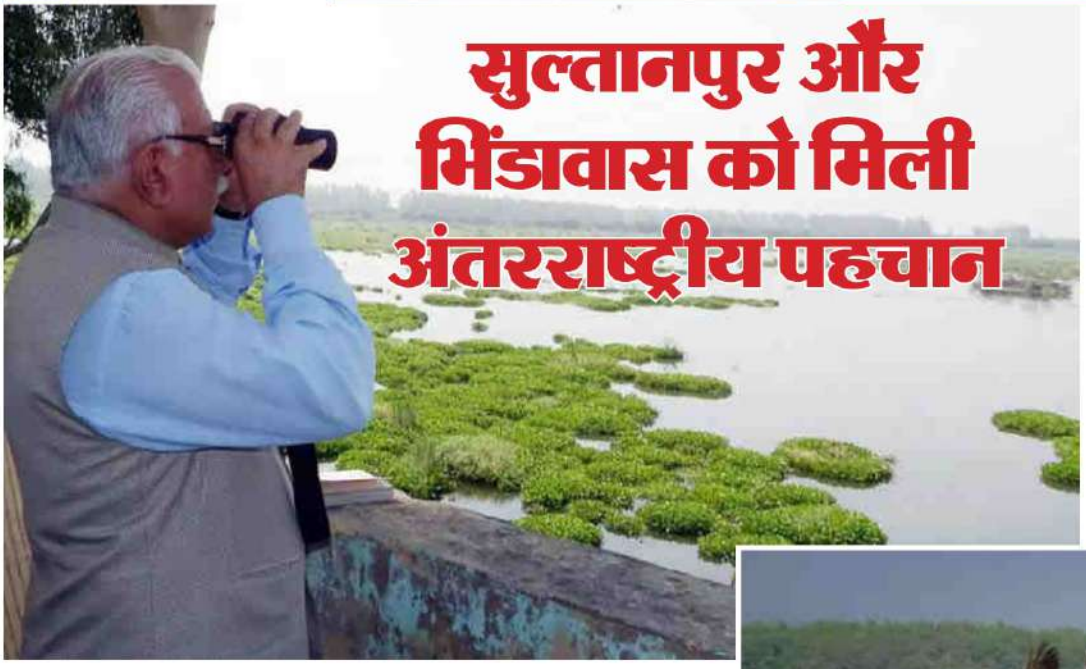

गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तथा झज्जर जिले में भिंडावास अभ्यारण्य की आर्द्रभूमि को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है।

शीतकालीन मौसम में ये दोनों क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए आरामगाह साबित होते हैं। पक्षियों को यहां सुरक्षित स्थल के साथ मछलियों के रूप में भरपूर भोजन भी मिलता है। यहां हर वर्ष 100 से अधिक प्रजातियों के लगभग 50,000 प्रवासी पक्षी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आते हैं।

सुल्तानपुर में प्रवासी पक्षियों की चहचाहट एक सुरम्य चित्रमाला सरीखी उपलब्ध करवाने का काम करती है जिसमें सारस क्रेन, डेमोइसेल ' क्रेन, उत्तरी पिंटेल, उत्तरी फावड़ा, रेड- क्रेस्टेड पोचार्ड, वेडर, ग्रे लैग गूज, गडवाल, यूरेशियन विजन, ब्लैक-टेल्ड गॉडविट आदि पक्षी शामिल होते हैं।

सुल्तानपुर कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के निवासी पक्षियों का भी स्थल है। धान के ग्रे फ्रेंकोलिन, ब्लैक फ्रेंकोलिन, इंडियन रोलर, रेड-वेंटेड बुलबुल, रोज-रिंगेड पैराकेट, शिकारा, यूरेशियन कॉलर डव, लाफिंग डव, स्पॉटिड ओवलेट, रॉक पिजन, मैगपाई रॉबिन, ग्रेटर कौकल, वीवर बर्ड, बैंक मैना, कॉमन मैना और एशियन ग्रीन बी-ईटर आदि पक्षी सुल्तानपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं।

भिंडावास अभ्यारण्य मीठे पानी की आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा स्थल है। सर्दियों के दौरान 80 प्रजातियों के 40 हजार से अधिक पक्षी भिंडावास में प्रवास के लिए आते हैं।

भिंडावास में सफेदा और बबूल के पेड़ हैं जो ओरिएंटल हनी-बजर्ड, पाइड किंगफिशर आदि पक्षियों के लिए बहुत अच्छा प्रवास प्रदान करते हैं।

हरियाणा सरकार की ओर से सुल्तानपुर और भिंडावास को छोटा आइसलैंड बनाने के लिए आर्द्रभूमि में कई विकास कार्य कराए गए हैं। झीलों से लंबी घास निकाली गई हैं और छोटे द्वीपों की बसावर पक्षियों के अनुकूल की गई है।

इस क्षेत्र में पक्षियों के लिए लुभावने फाईकस और कीकर जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनस्पति को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा लंबे नीलगिरी के पेड़ मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। इन में पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। सुल्तानपुर झील में सारस सहित कई पक्षियों ने प्रजनन शुरू कर दिया है।

रामसर ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर के पास एक तटीय शहर है। यह आर्द्रभूमि जल विज्ञान चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पर्यावरण को शुद्ध करते हुए प्रकृति की गोद के रूप में जाना जाता है। प्रवासी जलपक्षियों के लिए आर्द्रभूमि में आवास के नुकसान और गिरावट को ध्यान में रखते हुए रामसर शहर में 1971 में सम्मेलन हुआ था। इसके अंतरराष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए आर्द्रभूमि पर सन 1975 में एक संधि लागू हुई। यह संधि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए मजबूत ढांचा प्रदान करती है।

रामसर कन्वेंशन के दौरान दुर्लभ और अद्वितीय आर्द्रभूमि स्थलों को नामित किया गया है जो जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। बताया गया कि एक बार इन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की कन्वेंशन की सूची में जोड़ा जाये तो इन्हें रामसर साइट के रूप में जाना जाता है।

'रामसर' एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टैग है, जो आर्द्रभूमि को उसके पारिस्थितिक महत्व के लिए अंतरराष्ट्रीय महत्व प्रदान करता है। इस प्रकार हरियाणा की आर्द्रभूमि पहली बार विश्व स्थल के पटल पर आई हैं।

वेटलैंड्स क्या हैं

नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है।

आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से होकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है।

क्या होगा लाभ

अंतरराष्ट्रीय मान्यता के अलावा, रामसर टैग को पर्यावरण-पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करेगा क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र या उसके व्यवहार में परिवर्तन के लिये किसी भी खतरे का अर्थ अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी होगी। यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय शोध एवं अध्ययन का भी विषय बन जाएगा।

संवाद ब्यूरो

सुण छबीले बोल रंगीले

बिना पढ़ाई कामयाबी कोन्या भाई

छबीला- रसीले आज तो किमे चिकणा-चिकणा मुंह होरया सै। लागै सै भाभी नै रोटी की पापड़ी तलै घी धरकै खुआ दिया?

-ना भाई घी तो कोनी खुआया, पर सुसराड़ तैं कोथली आई थी। उसमैं मलाई आला घेवर था। सुवाद सुवाद में घणाए जीमग्या।

-मेरे बटे, मैं भी देखूं आज तो ढंग भी किमे टिका-टिकाकै धरै सै। और के आया कोथली में?

-भाई छबीले, और तो घर आली के सूट थे, उनतै म्हारा के काम। हां, मेरे खातर एक कुड़ता-पजामा जरुर भेज राख्या सै मेरी सासू नै।

-अरै तूं खाण-पीण की बात कर। सुहाली गुलगुले कोन्या भेजे के?

-ना भाई सुहाळी गुलगुले कोन्या, दो किलो पतासे भेज राखे सैं। उनमैं कौण मसूड़े फड़वावै।

-चाळै पाटगे। पहल्यां सुहाळी गुलगुले आया करते। वे बहुत बढ़िया लाग्या करते। सामण के दिनां में वे खाणे भी जरुरी होया करैं। सरसम के तेल में पके हुए पकवान खाणे तैं बरसात के दिनां में होण आले चर्म रोगां तैं बचाव होया करै। तीजां पै इस तरह के पकवान बणाने की परंपरा उएं नहीं सै। म्हारे बुजूर्गां नै बहुत सोच समझकै ऋतु अनुसार पकवान बणाए थे।

-म्हारे देस में हर तीसरा आदमी बैद्य सै। उनमैं तै एक तूं भी। तनै घेवर ना मिल्या होगा। ज्याहें तै भाषण दे सै। चिंता ना करै, घर कान्या चालैंगे, तेरी भाभी नै बचाकै धर राख्या सै।

अरै, छबीले, न्यू बता। आज काल यू पेपर लीक मामला बोहत सिर ठार्‌या सै। विधानसभा मं बी चोखी बहस होई। एक अखबार में तो न्यू भी लिख राख्या था अक ये पेपर कई कई लाख रुपयां में बिके।

-भाई रसीले, पेपर लीक तो पहल्यां भी होया करते। पर पहल्यां नौकरियां के कम और पीएमटी वगैरह के घणे होया करते। क्यूंके, पीएमटी के पेपरां में तो किसे की सिफारिश चाल्या नहीं करती। जो घणे नंबर लेज्याता उसका एडमिशन होज्याता। ना पढणिए बालक और के करते। पेपर लीक कराते, चाहे कितणे ए पीस्से देणे पड़ते। नौकरियां खातर परीक्षा का कोई झंझट ए ना था। जिसकी सिफारिश होती या घर का ब्यौंत होता तो सरकारी नौकरी लाग ज्याया करता।

- पर ईब घणे केस होण लाग गे।

- भाई, जिबतैं इस सरकार ने मेरिट के बेस पैं भर्ती करणी शुरू करी सैं, जिबतै ये पेपर घणे लीक होण लागगे। साच्ची बात यो सै अक पढणिए बाळक बहुत कम सैं, अर ना पढणिए घणे सैं। पढ़णा भी नहीं और सरकारी नौकरी भी लागणा। न्यू तो फेर ना पढणिए बाळक योए काम करैंगे।

-पर छबीले इतणे महंगे पेपर क्यूकर खरीदैं सैं?

-भाई, नौकरी तो पिस्सां में मिलती कोन्या। पेपरां में पास होणा पड़ैगा, वो भी घणे नंबरा तैं। इसलिए पेपर महंगे बिकगे। पर के होया। सरकार और बाळकां कै तो इतणाए नुकसान होया अक दोबारा पेपर लेणा और देणा पड़ैगा। पर जो इस कांड में थ्यागे, उनकी तो जिंदगी ए बेकार हो ज्यागी। ईब सरकार नै यू नियम बी बणा दिया अक जो भी इस तरियां का कांड करैगा उसनै जेल तो होवैगी, घर परिवार की संपत्ति भी कुर्क होज्यागी।

-ठीक कहै सै छबीले, ईब न्यू बता, पढणिए बाळकां नै के कसूर कर राख्या सै? वै तो दिन रात मेहनत करैं और ठोठ बाळक आगै चले जां। यो परपंरा तो टूटणी चाहिए। और टूटैगी। सरकार इनका कुछ न कुछ तो इंतजाम बांधैगी।

-रसीले, सिस्टम मं गलत परंपरा का यु नतीजा सै अक निरे मास्टर, कर्मचारी और अफसर इसे सैं अक उननै कक्खा नहीं आता। पढ़े लिखे आगै ना आवैंगे तै तालिबान मं और म्हारे मं फर्क के रहज्यागा?

-हां छबीले पुराणे रोग की जड़ कटण में टैम तो लागै सै।

-रसीले, चाल ईब घर नै, मेरे घेवर न ना भूल जाइये।

-मनोज प्रभाकर

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com